(iv) Supply of Improved Toolkits to Rural Artisans (SITRA)

(b) Loan schemes under IRDP are not free of interest. Immovable securities are not required for loans sanctioned for creation of movable assets upto a limit of Rs. 25,000/-. For loans above Rs. 25,000/ •inunovable securities .will be required. However, in cases where movable assets are not created (e.g. dug wells, development of land etc.), mortgage of land/ third party guarantee, is required as security even for loans below Rs. 25,00(1/

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

4712. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के (डी0पी0ए0पी0) के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं और किस सीमा तक प्राप्त किया गया हैं;

(ख)आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्ष –वार कितनी ण्धनराशि आवंटित की गई हैं;

(ग)उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्छ के सीमावर्त्ती जिले को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कल कितनी धनराशि की मांग की गई थी; और

(घ)यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल) : (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भूमि विकास, जल संसाधन

विकास, वनरोपण एवं चरागाह विकास के माध्यम से कार्यक्रम के क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार का विकास करना हैं। तदनुसार, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर 1994-95 तक भूमि विकास, जल संसाधन विकास, वनरोपण तथा चरागाह विकास के अंतर्गत देश में उपचारित वास्तविक क्षेत्र नीचे दिया गया हैं:-

	(000 हैक्टेयर में)
(1) भूमि विकास :	3444.16
(2) जल संसाधन विकास :	1155.84
(3) वनरोपण एवं चरागाह :	2327.68

उसके बाद सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई 4362 वाटरशैड विकास परियोजनाएं अभी तक चल रही हैं। उनके पूरा होने के पश्चात प्रत्येक परियोजना लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी।

(ख)आडवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डी0पी0ए0पी0 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई वर्षवार राशि विवरण में दी गई हैं। (**नीचे देखिए**)

(ग)और (घ) 1995-96 तक कच्छ के सीमावर्त्ती जिले को डी0पी0ए0पी0 के अंतर्गत आबंटित राशि 30.08 करोड़ रूपए थी। उसके बाद कच्छ में डी0पी0ए0पी0 का कार्य डी0डी0पी0 को सौंप दिया गया। डी0पी0ए0पी0 के लिए निधियां निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही आबंटित की गई थी।

विवरण

डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत केन्द्रीय रिलीज

(रूपए लाख में)

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज
1.आंध्र प्रदेश	631.50	1201.50	1093.96	2106.55	2619.63
2. बिहार	382.87	434.11	568.13	724.71	34.00
3.गुजरात	371.44	559.12	617.35	1013.96	731.06
4.हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	66.50	194.00
5. जम्मू कश्मीर	166.80	111.37	266.75	260.29	198.00

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज
6.कर्नाटक	571.55	846.46	1034.00	1159.04	493.55
7.मध्य प्रदेश	44.50	575.39	672.50	1938.70	2118.94
8. महाराष्ट्र	627.35	967.54	1109.00	1721.31	1260.73
9. उड़ीसा	430.47	421.17	516.50	403.84	295.00
10. राजस्थान	256.99	519.51	426.50	643.77	152.00
11. तमिलनाडु	365.26	682.17	622.12	532.49	1223.56
12. उत्तर प्रदेश	693.00	1036.53	1148.78	1093.16	1649.57
13. पश्चिम बंगाल	155.15	229.88	302.86	230.33	28.29
14. हरियाणा*	67.50	101.25	112.50	15.41	1.86
कुल	5124.38	7686.00	8490.85	11910.06	11000.19

*इसे अब डी0पी0ए0पी0 से बाहर कर दिया गया हैं।

Housing development etc. in villages

4713". SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state the steps proposed to accelerate non-farm activity and housing development in villages?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): The Ministry is implementing Indira Awaas Yojna with the objective of providing dwelling units to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Freed bonded labourers and Non-SOST poor below poverty line living in rural areas. The budgetary allocation for Rural Housing has been hiked by Rs. 410 crore in 1998-99 over the previous ygar, to Rs. 1600 crore. In addition, there are opportunities for engaging in off-farm activities by tapping the range of wage/self-employment schemes.

Drinking water facility in the villages of Gujarat

4714. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT; Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of villages in gujarat having proper drinking water facility round the year;

(b) the details of villages having seasonal difficulty; and

(c) the number of villages which have been declared as having "No Source" of drinking water?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) to (c) The status of coverage of rural habitations of Gujarat with safe drinking water facilities as on 1.4.98 as per information furnished by the State Government is as under:—

Not covered habitation	1008
Partially covered habitation	5898
Fully covered habitations	23363